जलवायु परिवर्तन एशियाई और अफ़्रीकी क्षेत्रों में महिलाओं की एजेंसी (*विकल्पों के चयन और निर्णय की क्षमता*) को किस प्रकार कम कर रहा है

लेखक: यशी

https://indianexpress.com/article/explained/how-climate-change-is-reducing-womens-agency-in-asian-african-settings-6142037/

हाल ही में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाली महिलाओं पर गंभीर रूप से भारी पड़ रहा है।

इंग्लैंड के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किये गए अनुसंधान के अंतर्गत अफ्रीका और एशिया के "जलवायु परिवर्तन के तीन विशेष प्रभावित गर्म स्थलों (हॉटस्पॉट)" के 25 केस अध्ययनों का उपयोग किया गया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि किस प्रकार पर्यावरणीय बदहाली महिलाओं की विकल्प चयन करने और निर्णय लेने की क्षमताओं को कम कर रही है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन की क्षमता भी शामिल है, जो उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

एशियाई "हॉटस्पॉट्स" के तहत भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तजिकिस्तान देशों को शामिल किया गया, जबकि अफ्रीकी देशों के तहत केन्या, घाना, नामीबिया, माली, इथियोपिया और सेनेगल को शामिल किया गया। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और यूके के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह शोध अध्ययन 25 नवंबर को नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित किया गया था। (' ए क्वालिटेटिव कॉम्पेरिटिव एनालिसिस ऑफ विमेंस एजेंसी एंड ऐडेप्टिव कैपेसिटी इन क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन एशिया एंड अफ्रीका': नित्या राव और अन्य)

25 केस अध्ययनों में से 14 मामले अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के थे, जबकि छह पहाड़ों और ग्लेशियर-आधारित नदी बेसिनों के और पांच डेल्टा क्षेत्रों के थे। इन सभी क्षेत्रों को लगातार किसी न किसी प्रकार के पर्यावरणीय जोखिमों जैसे सूखा/अकाल, बाढ़, अनियमित वर्षा, भूमि कटाव और भूस्खलन, और ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ आदि का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों की प्रमुख आजीविकाओं में कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ना आदि शामिल है, जो आमतौर पर श्रमिक मजदूरी, छोटे-मोटे व्यापार और रोजगार पलायन पर गए परिवार सदस्य द्वारा भेजे गए पैसों का सहारा लिए होती है या कहें कि उनसे पूरक होती है।

कृषि का 'महिलाकरण (फेमिनाइजेशन)'

जलवायु परिवर्तन ने मौसम की प्रकृति/व्यवहार को अनियमित कर दिया है और साथ ही मिट्टी और पानी के गुण को बदल दिया है, जिससे खेती जैसे व्यवसाय कम टिकाऊ हो चले हैं। सामान्यतः, पुरुष बेहतर काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं, और चूंकि खेती को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए महिलाएं वहीं रुक जाती हैं, और एक ऐसी गतिविधि में अपना अतिरिक्त श्रम झोंकती हैं जो अब आर्थिक रूप से उतनी उत्पादक नहीं रह गयी होती है।

खेती का यह कार्य उनके अपने घर-परिवारों की देखभाल एवं अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के अतिरिक्त होता है, और इस काम में उनकी मदद करने के लिए कोई पुरुष साथी नहीं होता है – इस अतिरिक्त कार्य के लिए उनको अपने स्वास्थ्य, पोषण और आराम के समय के साथ समझौता करना पड़ता है जो उनके कल्याण और खुशहाली के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अध्ययन यह भी प्रस्तुत करता है कि महिलाओं का इस बात पर बहुत कम नियंत्रण है कि वे अपने कमाए हुए पैसों को कैसे खर्च करें, या फिर यह निर्णय लेना कि खेत पर किस तरह की फसल लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, अर्ध-शुष्क क्षेत्र वाले देश केन्या में जब पुरुष बेहतर चरागाहों की तलाश में पशुधन के साथ दूर चले जाते हैं, तो महिलाएं दूध के "उपभोग और बिक्री के लिए उसपर अपना नियंत्रण खो देती हैं, और अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है"।

पुरुषों के पलायन करने के कारण अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन उनकी आय जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और अस्तित्व को सुनिश्चित करने में ही खर्च हो रही है, और न वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने की उनकी क्षमता में मदद कर रही है, और न ही जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन में सहयोग कर पा रही है।

अध्ययन के अनुसार, "भले ही अनुकूल घरेलू मानदंड कार्यबल में महिलाओं की बेहतर भागीदारी और घरेलू निर्णय लेने में उनका पक्ष रखने के लिए साथ दे रहे हों, घरेलू गरीबी और पर्यावरणीय तनाव महिलाओं की एजेंसी को दबाने के लिए एक जुट होते ही दिखाई देते हैं,"।

केन्याई महिलाएं घरेलू आय में सहारा देने के लिए काम तो कर रही हैं, लेकिन नशीले पदार्थों के व्यापार और यौन कार्य जैसे जोखिम भरे कार्यों में नौकरी करके। माली और घाना में, महिलाएं शुष्क भूमि पर काम करती हैं जो अक्सर उधार ली हुई होती है, उसमें कोई निवेश नहीं होता कि जिससे उसे पर्याप्त रूप से उत्पादक बनाया जा सके और उनके श्रम को उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

महिलाओं को निराश करती संस्थाएं

हालांकि अधिक से अधिक महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, लेकिन किसान संघ और बाजार पुरुषों द्वारा ही नियंत्रित हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, सहायता-सामग्री वितरण और स्थानीय शासन इकाइयों में पुरुषों का प्रभुत्व होता है, और सामग्री प्राप्ति में महिलाओं को पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर होना पड़ता है। अध्ययन के अनुसार, भारत में कई ग्रामीण स्थानीय निकाय के पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनके निर्णय काफी हद तक पुरुषों द्वारा ही तय किये जाते हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि घाना में, राज्य के हस्तक्षेप अधिकतर "समुदायों के भीतर पारंपरिक सामंजस्य और महिलाओं की अधिक लाभ देने वाली विविध आजीविकाओं में कार्य कर पाने की क्षमता दोनों को ही तोड़ने में जुटे लग रहे थे। नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित करना, और आमतौर पर पुरुषों द्वारा नियंत्रित औपचारिक विस्तारित सेवाएं प्रदान करना, उन्होंने उन्हीं सांस्कृतिक मानदंडों को मजबूत किया जो महिलाओं को इन क्षेत्रों से बाहर करते थे।"

बांग्लादेश में गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, नियोजित पुनर्वास के नाम पर राज्य के हस्तक्षेपों ने निर्यात प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नौकरियों उपलब्ध कराकर, जिन्हें आमतौर पर पुरुषों द्वारा ही प्राथमिकता दी जाती थी, "महिलाओं की एजेंसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया"।

शोधकर्ताओं के अनुसार, महिला स्वयं सहायता समूह "अक्सर संख्या में सीमित होते हैं और उनके प्रभावी और टिकाऊ होने के लिए उनमें आवश्यक क्षमता, कौशल और अवसरों का अभाव होता है, खासकर जहां व्यक्तिगत रूप में महिलाएं और समूह आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रणालियों पर निर्भर करते हैं ..."।

"हालांकि एक स्वयं सहायता समूह की सदस्यता अक्सर महिलाओं की एजेंसी के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह समूह के बाहर और उनके घरों के भीतर भी निर्णय लेने/अपनी बात कहने के अधिकार का अवसर प्रदान करे। इससे जाहिर है (सुझाव देता है)... कि जरूरी नहीं कि एक संस्था क्षेत्र में महिलाओं की एजेंसी (विकल्प चयन और निर्णय लेने की क्षमता) दूसरे संस्था क्षेत्र को निर्विरोध स्थानांतरित हो सकती है - यह स्थिति विशेष और सामाजिक ताने-बाने में बुना हुआ मसला है।"

हालांकि, अध्ययन कहता है कि कुछ सरकारी उपाय, जैसे कि भारत में खाद्यान्न/राशन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था, या नामीबिया में पेंशन और सामाजिक अनुदान देना आदि उपाय महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए और उन्हें अधिक खर्च करने की शक्ति प्रदान करके महिलाओं को अधिक एजेंसी (विकल्प चयन और निर्णय लेने की क्षमता) प्रदान करते हैं।